



वर्ष:- 02, अंक:-247, पृष्ठ:-08, मूल्य:- 2 रु.

लखनऊ, गुरुवार 20 फरवरी 2025

फर्जी तरीके से पुलिस की वर्दी पहन कर सोशल...06

समाज में सोशल मीडिया का महत्व के लिए परिषदीय विद्यालय...02

दिल्ली में अब रेखा राज

► रेखा गुप्ता पहली बार विधायक बनी, अब दिल्ली सीएम

नयी दिल्ली। दिल्ली में मुख्यमंत्री पद के लिए भजाया में पहली पासंद बनकर उभरी रेखा गुप्ता की है? वे मूल रूप से कहाँ की रहने वाली हैं और दिल्ली से उनका नाता कितना पुराना है? इसके अलावा रेखा गुप्ता की पढ़ाई कहाँ-कहाँ हुई है और उनका सियासी सफरनामा क्या रहा है? आइये जानते हैं, दिल्ली में विद्यासभा चुनाव के नतीजे आए 11 दिन का समाप्ति विद्यालय...02

पेशे से वकील हैं रेखा गुप्ता

देखा गुप्ता

उम्र: 50

सीट
शालीमार बाग

संपत्ति
5.31 करोड़
शिक्षा
एलएलबी
पेशा
वकालत

बीच राजनीतिक गलियारों में कई नेताओं के मुख्यमंत्री बनने की अटकलें लगाई गईं। इनमें सबसे बड़ा दावा रेखा गुप्ता की पढ़ाई की विद्यालय से आया है। इसके अलावा रेखा गुप्ता की पढ़ाई कहाँ-कहाँ हुई है और उनका सियासी सफरनामा क्या रहा है? आइये जानते हैं, कौन है रेखा गुप्ता? रेखा गुप्ता दिल्ली की शालीमार बाग विधानसभा का कोई नेता मुख्यमंत्री बना है। इस

दिल्ली में मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनी रेखा गुप्ता की है? वे मूल रूप से कहाँ की रहने वाली हैं और दिल्ली से उनका नाता कितना पुराना है? इसके अलावा रेखा गुप्ता की पढ़ाई कहाँ-कहाँ हुई है और उनका सियासी सफरनामा क्या रहा है? आइये जानते हैं, कौन है रेखा गुप्ता? रेखा गुप्ता दिल्ली की शालीमार बाग विधानसभा की अगली मुख्यमंत्री होगी। 20 फरवरी की वे दिल्ली के रामलीला मैदान में शाश्वत लंगी। यह भजाया ने भी उन्हें सीएम पद के लिए 26 साल बाद है, जब दिल्ली में भजाया ने यह जाना अहम है कि आखिर

केंद्र ने आपदा प्रभावित पांच राज्यों के लिए 1554 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की



केंद्रीय सहयोग को मंजूरी दी है जो वर्ष के लिए राज्य आपदा मोर्चा में उपचाल प्राप्तिक शेष राशि से 50 प्रतिशत के समायोजन के अधीन है। 5.31 करोड़ रुपए की वाली राशि से 5 राज्यों को आयोजित करना है। इसके अलावा रेखा गुप्ता की पढ़ाई कहाँ-कहाँ हुई है और उनका सियासी सफरनामा क्या रहा है? आइये जानते हैं, कौन है रेखा गुप्ता? रेखा गुप्ता दिल्ली की शालीमार बाग विधानसभा का कोई नेता मुख्यमंत्री बना है। इस

संपादकीय

बचपन पर भारी रस्मार्टफोन

तकनीक के जरिये विकास की अंधी दौड़ में हम बहुत कुछ खो भी रहे हैं। इंसान कभी मशीन से संचालित नहीं हो सकता। मानवीय संवेदनाएं और अहसास कभी कृत्रिम नहीं हो सकते। दूसरे शब्दों में कहें तो कोई तकनीक, मशीन व उपकरण सहयोगी तो हो सकते हैं, मगर मालिक नहीं हो सकते। कमोबेश यही बात शिक्षा में तेजी से बढ़ते स्मार्टफोन के उपयोग और उसके घातक प्रभावों को लेकर कही जा सकती है। निस्संदेह, शिक्षा के बाजारीकरण और नई शैक्षिक परिपाठी में मोबाइल की अपरिहार्यता को महंगे स्कूलों ने स्टेटस सिंबल बना दिया है। लेकिन हालिया वैश्विक सर्वेक्षण बता रहे हैं कि पढ़ाई में अत्यधिक मोबाइल का प्रयोग विद्यार्थियों के लिये मानसिक व शारीरिक समस्याएं खड़ी कर रहा है। निस्संदेह, विभिन्न ऑनलाइन शैक्षिक कार्यक्रमों के चलते छात्र-छात्राओं में मोबाइल फेन का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। तमाम पब्लिक स्कूलों ने ऑनलाइन शिक्षा के लिए

मोबाइल फेन का इस्तमाल आनवाय तक बना दिया है। कमोबेश सरकारी स्कूलों में ऐसी बाध्यता नहीं है। लेकिन वैश्विक स्तर पर किए गए सर्वेक्षण से यह तथ्य सामने आया है कि स्मार्टफेन एक हद तक तो सीखने की प्रक्रिया में मददगार साबित हुआ है, लेकिन इसके नकारात्मक प्रभावों को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इसमें दो राय नहीं कि एक समय महज बातचीत का जरिया माना जाने वाला मोबाइल फेन आज दैनिक जीवन की जरूरतों को पूरा करने वाला बेहद जरूरी उपकरण बन चुका है। खासकर कोरोना संकट के चलते स्कूल-कालेजों के बंद होने के बाद तो यह पढ़ाई का अनिवार्य हिस्सा बन गया। तब लगा था कि इसके बिना तो पढ़ाई संभव ही नहीं है। लेकिन नादान बच्चों के हाथ में मोबाइल बंदर के हाथ में उस्तरे जैसा ही है। जाहिरा तौर पर ये उनके भटकाव और मानसिक विचलन का कारण भी बन सकता है। अब इसके मानसिक व शारीरिक दुष्प्रभावों पर व्यापक स्तर पर बात होने लगी है। यहां तक कि आस्ट्रेलिया समेत तमाम विकसित देश स्कूलों में मोबाइल के उपयोग पर रोक लगा रहे हैं। अब तो यूनेस्को अर्थात् संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन की दुनिया में शैक्षिक स्थिति पर नजर रखने वाली टीम ने भी स्मार्टफेन के उपयोग से विद्यार्थियों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों पर चिंता जतायी है। इसकी रिपोर्ट भारत में शिक्षा के नीति-नियंताओं की आंख खोलने वाली है। यूनेस्को की टीम के मुताबिक बीते साल के अंत तक कुल पंजीकृत शिक्षा प्रणालियों में से चालीस फीसदी ने सख्त कानून या नीति बनाकर स्कूलों में छात्रों के स्मार्टफेन के प्रयोग पर रोक लगा दी है। दरअसल, आधुनिक शिक्षा के साथ कदमताल की दलील देकर तमाम पब्लिक स्कूलों में मोबाइल के उपयोग को अनिवार्य बना दिया गया। निससंदेह, आधुनिक समय में स्मार्टफेन कई तरह से शिक्षा में मददगार है। लेकिन यहां प्रश्न इसके निरंकुश प्रयोग का है।

साथ ही दुनिया में बेलगाम इटरनेट पर परोसी जा रही अनुचित सामग्री और बच्चों पर पड़ने वाले उसके दुष्प्रभावों पर भी दुनिया में विमर्श जारी है। जिसमें प्रश्न बच्चों की निजता का भी है। वहीं प्रश्न ज्यादा प्रयोग से बच्चों के दिमाग व शरीर पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों का भी है। निस्संदेह, शिक्षकों व अभिभावकों की देखरेख में सीखने की प्रक्रिया में स्मार्टफेन का सीमित उपयोग तो लाभदायक हो सकता है। लेकिन इसका अंधाधुंध व गलत उपयोग घातक भी हो सकता है। दरअसल, स्मार्टफेन में वयस्कों से जुड़े तमाम एप ऐसे भी हैं जो समय से पहले बच्चों को वयस्क बना रहे हैं। उन्हें यौन कुंठित बना रहे हैं। बड़ी चुनौती यह है कि बच्चों की एकाग्रता भंग हो रही है। बच्चों में याद करने की क्षमता घट रही है। ऐसे में जब शिक्षा में स्मार्टफेन का उपयोग टाला नहीं जा सकता, लेकिन उसका नियंत्रित उपयोग तो किया ही जा सकता है। निस्संदेह उसका उपयोग सीमित किया जाना चाहिए। संकट यह भी कि मोबाइल पर खेले जाने वाले ऑन लाइन गेम जहां बच्चों को मैदानी खेलों से दूर कर रहे हैं, वहीं स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर डाल रहे हैं। निश्चित तौर पर फेन छात्र-



ਮਾਣੁਸ਼ ਮਿਸ਼ਨ

आलेखः महेन्द्र दिवे

एक देश कैसे मरता है, अमृतसर में उत्तरने वाले अगेटिकों सैन्य विमान और उनमें हथकिडियों और बेडियों से बेध बैठे भारतीय नागरिक उसकी खुली निशानी हैं। मृत्यु के बाद एक भौतिक किया नहीं है। अगर किसी का मान-सम्मान खत्म हो जाए, किसी की प्रतिष्ठा धूल-धूसित हो जाए, तो वह शायद भी मरे के समान है। एक चलती-फिरती जिदा लाश। 140 कोइड की जनसंख्या वाले देश के नागरिकों को खुट उसकी ही धरती पर एक दूसरा देश हाथ-पांव बांधकर लाकर पटक रख है और उस देश के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इससे बड़ी विरंबना कोई दूसरी नहीं हो सकती है। दिलघस्प बात यह है कि यह देश इन्हीं सामाज्यवादी ताकतों के खिलाफ आपने मान-सम्मान, स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा के लिए लड़ते हुए खड़ा हुआ था। और उसी काम के लिए लाखों-लाख लोगों ने आपनी जानों की कुर्बानीया दी थीं। उन्होंने हसते-हसते फांसी के फटे चूमे थे। आखिर क्या मांग थी और क्यों लड़े अंगोजों के खिलाफ हमारे पुरुषे?

यही तो कि हम खुद अपने ऊपर शासन के लिए स्वतंत्र हैं और हमारे ऊपर कोई दूसरा राज करे, यह बात हमें गंवारा नहीं। वह भौतिक ही या कि नीतिगत स्तर पर, किसी तरह की गुलामी उन्हें मंजूर नहीं थी, जिसका नतीजा था कि अध्येत्रों को देखा छोड़कर भागना पड़ा और फिर स्वतंत्र रूप से देश ने अपने निर्माण की प्रक्रिया शुरू की। आज 75-76 सालों के दौरान न केवल ये लोकतंत्र के रूप में फला-फूला, बल्कि दुनिया के पैमाने पर भी अपनी एक हैसियत, प्रतिष्ठा और पहचान बनायी, जिसको मानवांशिक कहे जाने वाले दुनिया के तमाम देशों से लेकर छोटे-बड़े देशों ने स्वीकार किया। लेकिन 75 सालों के बाद एक ऐसी सरकार आयी है, जो इस पूरी प्रक्रिया को ही उलट देना चाहती है। पिछले 10 सालों में उसने न केवल लोकतंत्र को रौद्रने का काम किया, बल्कि देश को एक कष्टरूद धार्मिक राज्य में बदल देने की हर संभव कोशिश की। इस प्रक्रिया में न केवल सामाज्यवादी ताकतों के सामने समर्पण कर दिया गया, बल्कि देश की सही-सही प्रतिष्ठा को भी धूल-धूसित कर दिया गया। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई ऐसा देश, जो किसी देश के नागरिकों को हथकड़ी लगा कर उसी के देश भेज सके, बाक़जूद इसके उस देश का शासक उसकी यात्रा करने के लिए तैयार हो जाएगा? और इस कड़ी में वह सब कुछ मानने के लिए तैयार हो जाएगा, जो सामने वाला उसको निर्देशित करेगा? लेकिन ऐसा हुआ। और यह सब कुछ मोटी जी ने किया। लेकिन शायद मोटी जी को पता नहीं है कि जब आप ऐसा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो सामने

वाला भी आपकी हैसियत का अंदाज़ा लगा लेता है और फिर उसी तरह से आपके साथ व्यवहार करने लगता है। हालिया दौरे में ट्रम्प का पीएम नोटी के साथ किया गया व्यवहार वही दर्शाता है। पूरे दौरे में ट्रम्प के लेख से यहीं लगा कि वह किसी हेड ऑफ स्टेट को नहीं बुलाए हैं, बल्कि उन्होंने एक गुलाम को न्योता दे रखा है, जिसको उनके निर्देशों पर घलने में कोई परेशानी नहीं है। वरना उसी के आस-पास आए तीन दूसरे राष्ट्राध्यक्षों का छाइट व्यापक के बाहर आकर उन्होंने जब अगवानी की, तो पीएम नोटी की भी कर सकते थे। लेकिन उन्होंने नहीं किया। गैरि, तेल और एफ-35 बेपकार आखिर वह किसको लाभ दिलाए। टैरिफ़ के मामले में भी वह रटी भर भी पीछे नहीं हटे। और नोटी हर चीज़ को सिर झुकाकर स्वीकार कर लिए। कहीं किसी एक मामले में भी विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा सके। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब पीएम नोटी, ट्रम्प से हाथ मिला रहे थे, तो उसी दैरान मार्टीय नागरिकों को उसी धरती पर हथकड़ी बांध कर डिपोर्ट करने की तैयारी चल रही थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तो संसद के भीतर बोला था कि वह इस मसले पर अनेकिंवि सरकार से बात करेंगे और इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि भारतीय नागरिकों के साथ किसी तरह का गलत व्यवहार न हो। लेकिन इस भौतिकों का वर्णन हुआ, जो देश की सभसे बड़ी पर्यायत को उन्होंने दिया था? क्या उन्होंने बात की? और नहीं की, तो उसके बारे में बताए। वयोंकि वर्णन पता, अनेकिंवि अधिकारियों के सामने डर के चलते उनके बोल ही नहीं फूटे हों। और अब बात हुई है और फिर भी वे तैयार नहीं होते। उसके बारे में देश को उन्हें बत चाहिए। फिर तो संसद और देश फैलै करेगा कि उस पर क्या किया जा चाहिए। हाँ, इस बीच बात हुई या नहीं, तो जयशंकर और सरकारी अमला जालेकिन भेजे गए प्रवासी भारतीयों अनेकिंवि सैनिकों की तरफ से ज़रूर दूसरा तर्क दिलावा दिया गया कि ये बेटे और हथकड़ियां खुट उनकी सुरक्षा लिए ही लगायी गयी थीं, वयोंकि नियमनियति से वे गुजर रहे हैं, उसमें वे ऐसी हरकत कर सकते हैं, जो खुट उन्हें लिए भी नुकसानदायक हो सकती। अब इससे बड़ा माज़ाक कोई दूसरा नहीं सकता है। चलिए, एकबारी आपका तर्क मान लेते हैं। तो फिर उन नियिला और बच्चों का वर्णन, जिनको आपने इस छूट दे रखी थी। क्या उनकी जान कीमत कम थी या कि फिर आप को उनका फिर नहीं थी? इस लिहाज से तो बच्चों लिए और ज्यादा जल्दी ही जाता लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल भारतीयों को उनकी औकात बताने सकता अपनाया गया है, जिससे अनेकिंवि की तरफ देखने की भी वो हिम्मत व जुटा सके। एक सवाल नोटी जी से ज़रूर पूछ जाना चाहिए कि आपके 17 हजार नागरिकों को अगर इसी तरह हथकड़ियां और बेड़ियां बांधकर ले जाएगा तो क्या आप कभी अनेकिंवि से राष्ट्रपति या फिर उसके दूसरे अधिकारियों से नजर से नजर मिलाकर बात बताएंगे? ये मत भूलिए, जिन्हें आप मान-सम्मान का ख्याल नहीं होता

दूसरे भी फिर उसकी फिर नहीं करते हैं। इसलिए आपकी इज्जत आपके साथ में होती है। क्या आप कभी सोच सकते थे, देश के दूसरे प्रधानमंत्री नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और यहां तक कि मनमोहन सिंह भी इस तरह की कोई शर्त मानने के लिए तैयार हो जाते? कर्तव्य नहीं! अनायास नहीं, बांगलादेश वार में जब अमेरिका के सातवें बड़े के आने की बात कही जाने लगी तो इंदिरा गांधी ने बयान दिया कि सातवें बड़ा आए या सातवां युद्ध नहीं लड़ेगा। मोटी जी यह साहस आप कर्यों नहीं दिखा सके? तैं बताता हूं, उसके पीछे क्या कारण है। दरअसल आप जिस आरण्यसांश और हिंदुत्व की धारा से आते हैं, उसने आजादी की लड़ाई में हमेशा अंदरौं का साथ दिया। आपकी पूरी मानसिकता ही गुलामी की है। आपने बाहर के जो असली दुर्मन थे, जो देश को लूट कर ले जा रहे थे, उन्हें कभी दुर्मन के रूप में देखा ही नहीं। आप हमेशा उनके देस्त बने रहे। आपने हमेशा उनका सहयोग किया। और यहां तक कि उनके लिए मुख्यबिधी तक की। इसलिए वो कभी भी आपको दुर्मन नजर ही नहीं आते। आपने अपने देश के भीतर ही अपने भाई-बंधुओं के बीच दुर्मन ढांच लिए हैं। जिनसे भाईचारे का रिश्ता है, उनमें आप नफरत और धूमा फैलाते रहते हैं। इसलिए आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले उस अपमान का एहसास ही नहीं है। और आप यह रहे हैं कि पूरा मामला रफा-दफा कर दिया जाए। इसकी किसी को कोई खबर ही न हो। और वह चर्चा का विषय ही न बने। इसलिए आपका कार्टून प्रकाशित करने वाली उस तमिल वेबसाइट को बैन कर दिया गया। जिसमें ट्रन्प के सामने आपके हाथों और पैरों में जंजीरे बांधकर कुर्सी पर बैठे दिखाया गया है। इसमें गलत व्याप है यही असली सच्चाई है। वह जंजीरे उन नागरिकों के पैरों और हाथों में नहीं बांधी गयी है, वो हमारे और आपके हाथों में बांधी गयी है। और देश के किसी नागरिक से पहले आपके हाथों में बंधी हैं, तर्कोंकि आप देश के मुखिया हैं और इस देश की संप्रभुता के दस्तक। अगर देश के साथ कुछ होता है, तो उसकी सबसे पहली जिम्मेदारी और जवाबदारी आपकी है लेकिन आप उसको लेने से भाग रहे हैं और आपने ही नागरिकों को अपराधी करार देकर अपनी जिम्मेदारी से फर्जीता पा लेना चाहते हैं। होना तो यह चाहिए था कि आप कोलंबिया के राष्ट्रपति की तरफ उसका प्रतीरोध करते और जैसा कि कोलंबिया के राष्ट्रपति ने किया है, इन अमेरिकी सैन्य विमानों को भारत की धरती पर उतारने ही नहीं देते। लेकिन आप तो ऐसा नहीं कर सके। लेकिन इस देश की जनता इसको स्वीकार करने नहीं जा रही है। अगली कोई खेप इस धरती पर नहीं उतरनी चाहिए। और इसके लिए जल्दी पड़े तो भारतीय विमानों को अमेरिका उन्हें लेने के लिए लेजा जाना चाहिए। और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है, तो भारतीय नागरिकों को यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए, याहे इसके लिए भले ही उन्हें घेरे इकट्ठा करना पड़े। और फिर उस पैसे से भारतीय नागरिकों को भारत ले आया जाए। जल्दी पड़े, तो इसके लिए एहसास धर्मात्मी अभियान भी चलाया जा सकता है।

मोदी जी, अगर देश का सम्मान बचा नहीं सकते, तो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते?

मोदी, ट्रम्प और व्यावसायिक हित

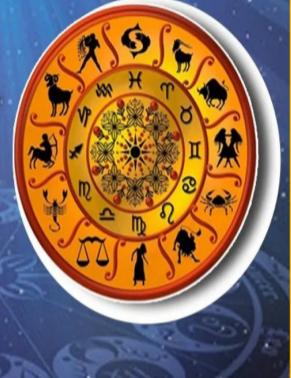
अरावन्द मोहन

शेयर बाजार में चल रहा माजूदा
दौर की गिरावट में बाजार के कुछ
बड़े और कुशल खिलाड़ियों को
कितने का नुकसान हुआ है यह
हिसाब अब आने लगा है। कई का
नुकसान लगभग एक तिहाई तक
का है पर कुल मिलाकर बाजार
इतना नहीं गिरा है। लेकिन ऐसे
शीर्ष वाले लोगों का नुकसान अगर
कुछ सौ करोड़ का है तो हमारे
शेयर बाजारों के सारे निवेशकों का
नुकसान दसेक लाख करोड़ रुपए
से अधिक का हो चुका है और
उसकी चर्चा कम है। यह पैसा आम
लोगों का तो है ही, उनके बैंक
जमा, प्राविडेन्ट फंड, साझा कोशिशें
और बीमा कंपनियों को चुकाए।
उनके प्रीमियम की रकम का है।
और आम तौर पर यह धन शेयर
बाजार के विशेषज्ञों के साथ ही
सरकार के इशारों पर बाजार में
लगता है, उसे चढ़ाता और गिराता
है। इस बार का भूचाल अमेरिकी
शासन के बदलाव से जुड़ा है
अर्थात डोनाल्ड ट्रम्प के पिछे से
राष्ट्रपति बनने के बाद लिए उन
फैसलों और आने वाले फैसलों की
आशंका से इसका रिश्ता है जिसे वे
अमेरिका को पिछे से महान बनाने
के अपने वायदे के हिसाब से ले रहे
हैं या लेने वाले हैं। इस बीच हमारे
रुपए को गोता लगाने से बचाने के
लिए (पिछे भी उसने अच्छी खासी
गिरावट दर्ज की है) रिजर्व बैंक ने
कितना दंड-प्राणायाम किया है वह
अलग हिसाब है पर उसने हमारी
गाढ़ी कमाई के हजारों करोड़ मल्य
के डालर बाजार में उतारे हैं। और
मोदी राज की शुरुआत में पच्चीस
हजार के रेट वाले सोना ने आज
प्रति दस ग्राम नब्बे हजार का स्तर
छूकर कितनों को रुलाया है, यह
हिसाब भी आसानी से लगाया जा

सकता हा। काइ उम्माद कर सकता है कि जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका यात्रा की और ट्रम्प से मिले (या उनके पहले विदेश मंत्री जयशंकर ने अमेरिका में अड्डा डाला था) तो वे जरूर महाबली अमेरिका के इस राष्ट्रपति से अपना दुखर्दद कहेंगे और अभी तक जारी अच्छे राजनीतिक संबंधों के आधार पर अपनी परेशानियों का समाधान चाहेंगे, अमेरिका-भारत संबंधों में इसके चलते खटास न आए, इसका इंतजाम करेंगे। ट्रम्प दोबारा चुनाव जीतकर कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वास और अमर्यादित व्यवहार पर उतरे लगते हैं, शपथ ग्रहण करने के साथ ही उहोंने दो सौ से ज्यादा बड़े फैसलों पर दस्तखत करके दुनिया को श्दहलाश दिया था और अभी भी उनका उत्साह जारी है। इस उत्साह को दुस्साहस बताने वाले कम नहीं है क्योंकि इससे अमेरिका का लाभधारा क्या होगा यह हिसाब नुकसान की तरफ जाता लगता है। कहा जाता है कि ट्रम्प इस बात से ज्यादा खुश न थे कि उनका मित्र माने जाने वाले मोदी ने बाइडन प्रशासन से भी अच्छा संबंध रखा और चुनाव हारने के कारण उनकी तरफ पीठ फेर लिया था। इसलिए मोदी और ट्रम्प की दोस्ती के पक्षधर इस बात को लेकर खुश हैं कि इस यात्रा में प्रधानमंत्री पुरानी गर्मजोशी हासिल करने में सफल रहे। बातचीत, व्यवहार, राजनीतिक शिष्टाचार से लेकर इस यात्रा में हुए समझौतों के आधार पर ऐसा नहीं लगता क्योंकि सारा हिसाब अमेरिका के पक्ष में ढाका हुआ है। और साझा प्रेस कांफ्रेंस में ट्रम्प ने जिस तरह से मोदी जी के प्रति व्यवहार दिखाया वह सामान्य न था, बल्कि कई बार तो यह खिल्ली

उडान के कराब तक पहुंच गया। और मोदी जी ट्रम्प प्रशान के करीबी उद्यमी एलन मास्क से मिलने और उनके भारत से व्यावसायिक रिश्ते बनाने को लेकर जितने बेचौन रहे हैं उसमें उनका व्यवहार भी सामान्य शिश्चार वाला न था। वे प्रधानमंत्री से भेट में अपनी पत्नी, बच्चों के साथ बच्चों की देखरेख करने वाली सहायिका को भी लेकर पहुंचे थे। और सामान्य निष्कर्ष यही रहा कि इस यात्रा से भारत- अमेरिकी दोस्ती में कोई कड़वाहट न आई या वैसा कुछ था तो वह खत्म हुआ लेकिन कुल मिलाकर अमेरिका लाभ की स्थिति में रहा। उसने मनमाने व्यावसायिक करार किए और भारत ने ज्यादा ना नुकर न करते हुए उन्हें स्वीकार किया। इसमें गैरजररुरी सैन्य सामग्री की खरीद का करार भी शामिल है और तेल समेत कुछ ऐसे सौदों का प्रसंग उठाना भी है जिनमें समझौता करना भारत को महंगा पड़ेगा। रूस या इराकी-कुवैती तेल हमें बहुत सस्ता और सुविधाजनक पड़ता है। जिस सवाल की चर्चा ट्रम्प- मोदी साझा प्रेस काफ़ेर्स में ज्यादा थी और जिस पर ट्रम्प ने भी मजा लिया वह हमारे उद्यमी गौतम अदानी के खिलाफ अमेरिका में चलाने वाले मामलों से जुड़ा था और जिस पर प्रधानमंत्री ने बहुत ही दार्शनिक किस्म का जवाब देकर बचते नजर आए। असल में इस दौर की वार्ता और समझौतों का बीज विषय यही लगता है और प्रधानमंत्री का वह जवाब मोदी सरकार के बचाव की मुद्रा को बताता है। बातचीत और समझौतों से पहले खबर आ गई कि अदानी के खिलाफ चल रहे मुकदमों में राष्ट्रित दखल देकर हमारे व्यवसायी को राहत देंगे। अडाना पर गलत सूचनाएं देकर अमेरिकी निवेशकों से धोखा कर और आंध्र प्रदेश सरकार व अधिकारियों को घूस देने व मामले दर्ज हुए थे। उससे एक हाहाकार पहले मच चुका था। और जब विदेश मंत्री जयशंकर ट्रम्प ने शपथ ग्रहण समारोह में भागीदारी करने गए थे तब यह हुआ जिसका मामला स्थानीय अदालत से उठकर फेडरल कोर्ट में आ गया था। मारा जाता है कि स्थानीय अदालत ज्यादा स्वायत्त हैं और फेडरल कोर्ट और कानून में राष्ट्रपति का दखल संभव है। इस अमेरिकी यात्रा और इस तरह के फैसले करने करने व तैयारी उसके पहले शुरू हो गई। और अभी भी चल रही है। अभी भी इस्पात और अल्युमिनियम पर सीमा शुल्क पच्चीस पैसेंटी करने की माथापच्ची चल रही है क्योंकि ट्रम्प ऐसा चाहते हैं। ट्रम्प विश्वव्यापार संगठन के जरिए बनाए गए वैश्विक व्यापार नियमों से खाली खफ है जबकि वाशिंगटन कंसनसेस से शुरूआत करके गैर और विश्वव्यापार संगठन बनवाया और उसकी मुश्किल शर्तें मनवायी में अमेरिका ने ही केन्द्रीय भूमिका निभाई थी। इस संगठन का सबब बड़ा चरित्र व्यापार संबंधों व द्विपक्षीय की जगह बहुपक्षीय बनाना था और इन शर्तों व मनवाने के लिए सख्त निगरानी और दंड-पुरस्कार की व्यवस्था बनानी थी। आज ट्रम्प इस सब परानी फेरते हुए संरक्षणवाद और द्विपक्षीय व्यापार पर जोर दे रहे हैं दुनिया इसी डर से कांप रही क्योंकि एक अनुमान के अनुसार सब कुछ ट्रम्प के अनुसार चला त अमेरिका की ही विश्वव्यापार हिस्सेदारी 15 से घटकर 12 पैसेंट रह जाएगी।

आज का राशीफल



मख्य निर्वाचन आयक की जल्दबाजी में नियुक्ति

जिस प्रकार से लोकतांत्रिक मर्यादाओं तथा परम्पराओं को ताक पर रखकर, जल्दबाजी में केन्द्र सरकार ने 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त (चीफ इलेक्शन कमिशनर- सीईसी) की नियुक्ति की है उससे चुनाव सुधार की उम्मीदों पर फिर से पानी फिर गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के 18 फरवरी को सेवानिवृत्त होने से पहले ही केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय में 17 फरवरी की शाम एक बैठक बुलाई, जिसमें प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के अलावा नेता प्रतिपक्ष भी शामिल हए।

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसके बैठक के लिए पहले ही आपका जाहिर कर दी थी, बावजूद इसके सरकार ने उन आपत्तियों को दरकिनार करते हुए न केवल बैठक की, बल्कि सोमवार देर रात नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त के तौर पर ज्ञानेश कुमार को नियुक्त कर दिया। इस नियुक्ति पर

भी विपक्ष सवाल उठा रहा है। 1988 बैच के केरल कैडर के आईएप्स अधिकारी ज्ञानेश कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय में अपने कार्यकाल के दौरान जम्मू-कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधानों को निरस्त किये जाने के बाद निर्णय को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और 15 मार्च, 2024 को निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला था। ये पहली बार है, जब मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023 के तहत हुआ है। इससे पहले बीते साल ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को नए कानून के तहत चुनाव आयुक्त चुना गया था। निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार का कार्यकाल कई किस्म के विवादों में घिरा रहा। आरोप लगे कि

उनके रहते आयोग ने भाजपा की सुविधानुसार चुनावी कार्यक्रम बनाना, सिर्फ विरोधी दलों के खिलाफ कार्रवाइयां करना, भाजपा के गलत कार्यों की अनदेखी करना, आचार संहिता का प्रतिपक्ष को दबाने में इस्तेमाल करना और विरोधियों को न सुनना जैसे कार्य किए। उनके दौर में हुए लगभग हर चुनाव में गड़बड़ी की शिकायतें विपक्ष ने कीं। ईवीएम में छेड़छाड़ से लेकर मतदाता सूची की गड़बड़ी जैसे गंभीर आरोपों के सवाल उठे, मतदान खत्म होने के कुछ घंटों के बाद वोटिंग का प्रतिशत बढ़ जाना, मतगणना बीच में रुकने या धीमी होने के बाद कुछ ही मिनटों में हारती हुई भाजपा की सीटों का इतना बढ़ जाना कि वह राज्यों में सरकार बना ले आदि ऐसी घटनाएं हैं जो हमेशा संदेह के घेरे में रहेंगी। विपक्ष ने भाजपा की जेबी संस्था, चूना आयोग जैसे शब्द चुनाव आयोग के लिए किए ताकि उसके आरोपों की गंभीर समझी जाए। लेकिन इन सब कोई असर संभवतः सरकार नहीं हुआ। लोकतंत्र के पक्ष में सारे लोग जो एक स्वतंत्र, मजबूत और निष्पक्ष चुनाव आयोग उत्तमीद राजीव कुमार के जाने बाद लगाये बैठे थे, वे इसलिए मायूस हैं क्योंकि उन्हें वारियर बदलाव की अब कोई उत्तमीद रह गयी है क्योंकि उसीसी का उसी धारा में तैरना लगभग तय माना जा रहा सीईसी के रूप में ज्ञानेश कार्यकाल जनवरी, 2029 तक रहेगा। इस दौरान उनकी देखेंगे में लगभग 20 विधानसभा चुनाव होंगे तथा अगली लोकसभा लिये 2029 में होने वाली सभी तैयारियां वे करके जायेंगी यदि उन्हें सेवा विस्तार न मिलता तो। ऐसा तभी होगा यदि वे राजीव कुमार की बनाई लीन से हटकर काम करेंगे जिसका उत्तमीद कम है। केन्द्रीय निर्वाचन

आयोग हमेशा भाजपा सरकार की जेब में बनी रहे, इसकी तैयारी पहले से कर ली गयी थी। 2023 में सीईसी नियुक्ति अधिनियम में संशोधन कर चयन समिति से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया। इसका उद्देश्य साफ था कि चयन प्रक्रिया में बहुमत सरकार का बना रहे। इसे लेकर विपक्ष, खासकर कांग्रेस आपत्ति जताती रही है। इसके खिलाफ शीर्ष कोर्ट में एक याचिका भी लगाई गयी है जिस सम्बन्ध में तीन सुनवाईयां हो चुकी हैं और अगली सुनवाई बुधवार 19 फरवरी को ही निर्धारित है। कहीं उच्चतम न्यायालय इस नियम को अवैध न ठहरा दे, इसलिये अदालती फैसले हेतु ठहरने की बजाय (और आशंका में) सोमवार को बैठक बुलाकर राहुल की कड़ी आपत्ति के बावजूद नया सीईसी घोषित किया गया। सरकार रुक सकती थी क्योंकि फिलहाल देश में कोई चुनाव नहीं है। केवल बिहार का होगा- वह भी इस साल के अंत में। आधी रात को राष्ट्रपति द्वौपदी मुम् ने हस्ताक्षर भी कर दिये। इसलिये राहुल ने इस प्रक्रिया को शुरूमानजनक व अशिष्य बतलाया है जो कि गलत नहीं है। राहुल गांधी ने अपनी आपत्ति का एक पत्र केंद्र सरकार को दिया है। वहाँ कांग्रेस ने एक ट्वीट में आधी रात का तखापलट शीर्षक के तहत कई बिंदुओं में समझाया है कि कैसे मोदी-शाह ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर कब्जा किया है। कांग्रेस ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट को दरकिनार करने से लेकर आधी रात की नियुक्ति तक, मोदी और शाह ने दिनदहाड़े सबसे बड़े चुनावी तखापलट को अंजाम दिया है। यह बेहद गंभीर आरोप है जो कांग्रेस ने लगाया है, अब देखना होगा कि अदालत इस आपत्ति का संज्ञान लेती है या नहीं।

रुबीना दिलैक

मां बनना मेरे लिए घर बैठने का बहाना नहीं है, 10वें दिन ही फिल्म प्रमोट कर रही थी



अभिनेत्री रुबीना दिलैक अपनी जुड़वा बैटियों की परवरिश और काम के बीच तालमेल बिटा रही है। वह एशियाई शो लेलाफर शेफ सीजन 2 शॉ में नजर आ रही है।

रुबीना का मानना है कि घर के काम सभी को आने वाहिए।

रुबीना दिलैक का कहना है कि बैटियों की परवरिश में पति

अभिनव का बड़ा सहयोग मां बनने के बाद भी रुबीना का काम करने का जुनून बरकरार है घर में काम में रुबीना और अभिनव दोनों का बराबर का योगदान है जब-जब

मैं काम करती हूं, तब-तब मैं खिलती हूं, यह कहना है, अपनी

साल भर की जुड़वा बैटियों की

परवरिश और काम के बीच

बखूबी तालमेल बिटा रही ऐश्वर्देस

रुबीना दिलैक का। छोटी बहू-

शक्तिरु अस्तित्व के अहसास की

और बिग बॉस 14 जैसे शोज में

अपनी अधिष्ठित छाप छोड़ने वाली

रुबीना इन दिनों रिपोर्टिंग शो

लाप्टॉप शोफीजी 2 में नजर आ

रही है। बचपन में आप पढ़ाई

काफी फैक्स्ड थीं। आईएएस

बनना चाही थीं। मॉडलिंग भी

करती थीं। ऐसे में, कृषिगं

में भारत के हासिल की?

वैसे, अपनी तरफ़ यादवातर मारे बैटियों

को कापी पहले ही कुकिंग सिखाने

लगती हैं! आपने बिल्कुल सही

कहा। मेरी मम्मा भी बचपन से

ही हम तीनों बैटियों को खाना

बनाना, घर की सफई, घर की

देखरेख की शिक्षा दी है। हम

स्कूल से आते थे, तो एक बहन

रोटी बनाती थी, दूसरी सफ़र्व

करती थी और तीसरी काट

देती थी, तो हम मिल बांटकर

काम करते थे। हमारे परिवार में

खाना बनाना और घर की देखरेख

करना हमारी एजुकेशन का बहुत

अहम हिस्सा था और मुझे खुशी

है कि मेरे पैरेंट्स ने हमें वह शिक्षा

दी वर्याक कोई भी काम बड़ा या

छोटा नहीं होता है। आज भी

मुझे खाना बनाना पढ़े तो मैं

बनाता हूं। हालांकि, भगवान की

दया से आज हमें कुक मिल जाते

हैं। हेल्प मिल जाते हैं, मगर मेरा

मानना है कि घर के काम सभी

को आने चाहिए। चाह यो लड़का

हो या लड़की। इस मामले में मैं

कहूँगी कि अभिनव (पति अभिनव

शुर्वला) भी बहुत परिपूर्ण है।

उन्हें घर के सारे काम आते हैं।

वह खाना बना लेते हैं। कपड़े-

बत्तन साफ़कर लेते हैं, तो उनसे

भी मुझे बहुत प्रत्याहन मिलता

है कि वह यह पांच नहीं करते

हैं कि घर के काम करना

औरत की जिम्मेदारी है। यह

अच्छी बात है कि औरतों के

प्रति इस सोच में बदलाव

आ रहा है और अपने घर

में यह बदलाव देखा है। आप एक साल पहले ही जुड़वा बैटियों एवं और जीवा की मां बनी हैं। इसके बाबजूद, पॉडकार्ट से लेकर इस शो तक में लगातार सक्रिय है। एक घर और मां के डबल रोल के बीच कैसे बैलेस बना रही हैं?

देखिए, मेरी मजबूरी नहीं थी कि

मैं काम करूँ। मेरे लिए कोई

बैटियों से बाहर आने के बाद

होश में आई, तभी नर्स ने कहा

कि एक बैटी का डायपर बदलना

है और मुझे एक आवाज सुनाई दी

कि मैं करता हूं, मैं करता हूं।

पिछे, अभिनव आए और उन्होंने

उसका बहुत खुशी के साथ

उसका डायपर सफ़किया। पिछे

इंडस्ट्री ही या टीवी इंडस्ट्री लाग

टैग बड़ी जानी देते हैं। अभिनेत्री

रुबीना दिलैक को बास लेडी का

टैग मिला है। इस बारे में बात की

हमने उससे तो रुबीना ने हां

सकते हैं। इसके बाद दिलैक

बैहतरीन बिवाब दिलैक अपने

बैहतरीन बिवाब दिलैक आने के लिए

बैहतरीन बिवाब दिलैक बैहतरीन

बैहतरीन बिवाब दिलैक

